for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1978-79 was submitted last month only. As per terms of the Resolution setting up the Commission, the Report has to be placed on the Table of each House of Parliament and action is being taken to comply with the requirement.

Attacks on Harijans in Bihar

229. SHRI VIJAY KUMAR YADAV: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of incidents of attacks on Harijan reported during the current year in Bihar and the reasons therefor;

(b) the number of persons killed, loss of property etc. in each of these incidents;

(c) whether Government have given any compensation to the victims;

(d) the number of houses damaged and the assistance provided by the Government for their repairs; and

(e) the measures taken to bring the culprits to book to check recurrence of such incidents in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) According to information received from the Government of Bihar, the following crimes were perpetrated by members of non-Scheduled Castes against members of Scheduled Castes in the State during the months of January and February, 1980:

Month	Murder	Violence resulting in previous hurt	Rape	Arson or serious mischief in respect of property	Other I.P.C. offences
Jan. 80	5	13	5	19	72
Feb. 80	2	5	1	4	25

The State Government has further reported that the above information is incomplete as reports from some of the districts have not yet been received by them. They have stated that these incidents took place as a result of various causes such as land disputes, disputes regarding minimum wages group rivalry etc.

(b) 21 persons were killed in these incidents. 45 houses were destroyed. Domestic articles such as cloth and wooden furniture were burnt down and some domestic animals were also killed in arson cases.

(c) and (d). The State Government has reported that immediate relief in kind and cash were provided. Clothes and ration were given together with financial assistance for construction of new houses.

(e) The State Government has reported that all police and civil officials have been directed to give utmost attention to the problems of members of Scheduled Castes. Measures have been taken to apprehend guilty persons and complete investigation of cases quickly.

Foreign Conspiracy behind agitation and violent incidents in Assam

230. SHRI K. C. PANDEY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether conspiracy by the foreign countries is behind the agitation and violent incidents in Assam;

(b) whether it is also a fact that the conspiracy aimed at destroying the national unity was encouraged by the Janata and Lok Dal Governments;

(c) whether Government are taking necessary steps to contain this; and

(d) if so, the progress made so far in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (d). Allegations in this regard have been made. However, it is not easy to get conclusive proof in such matters. Government are keeping a careful watch over the situation.

पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बस्ती जिला में उद्योगों की स्थापना

231. **श्री के. सी. पाण्डेय** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग लगाने का विचार है;

(ग) क्या बस्ती पिछड़ा जिला है और यदि हां, तो वहां कौन-कौन से उद्योग लगाने का विचार है; और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए क्या-क्या सुविधाएं देने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना): (कछ से (घ). पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बस्ती, देवरिया, फैजबाद, गाजीपुर, गौंडा और जौनपुर को उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती वित्त तथा अन्य सुविधाएं पाने की पात्रता हेतु औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र समझा गया है। इन जिलों में से, बलिया, बस्ती तथा फैजबाद को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए चुना गया है। केन्द्र सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रदान करती है:—

(1) निवेश राज सहायता की केन्द्रीय योजना।

(2) अखिल भारतीय सावधिक ऋण देने वाले वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित किये गये हैं।

(3) कर संबंधी रियायतें।

(4) लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से मशीनरी की किराया खरीद।

(5) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श ।

(6) ब्याज राज सहायता ।

(7) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधायें ।

(8) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम ।

(9) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम ।

(10) जिला उद्योग केन्द्र ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1978 में 1 आशय पत्र और 6 औद्योगिक लाइसेंस तथा 1979 में 3 आशय पत्र और 2 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं । किन्तु, बस्ती में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1978-79 में कोई आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। किसी क्षेत्र का विकास करना राज्य सरकार का विषय है तथा यह बात जनता पर निर्भर करती है कि वह केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए आगे आये।

पार्टी का नाम, बनाई जाने वाली वस्तु, क्षमता, एकक के स्थान आदि सहित उन आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसेज, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसेज में तथा इंडियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर द्वारा प्रकाशित "मन्थली न्यूज लेटर" के परिशिष्ट में प्रकाशित किया जाता है । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।